नीमका जेल में स्वास्थ्य जांच का ड्रामा, केवल मैट्रो अस्पताल की विज्ञापनबाज़ी

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते सप्ताह नीमका जेल में बंद कैदियों के स्वास्थ्य की जांच का शिविर लगाया गया। बताया गया कि इसमें मैट्रो अस्पताल के तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर जांच उपकरणों सहित आये थे और कैदियों की जांच करके उन्हें मुफ़्त दवायें आदि भी दे गये थे। आने वाले डॉ. साधारण थे या विशेषज्ञ, अपने साथ उपकरण लाये थे या नहीं, दवायें दी थी या नहीं, इसकी सच्चाई केवल वहां बंद कैदी जानते हैं या जेल स्टाफ़। कैदी बेचारे तो बताने की स्थिति में नहीं और जेल स्टाफ़ किसी को बतायेगा क्यों?

जेल से बाहर आये एक कैदी ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जेल अधीक्षक अनिल कुमार अपनी छवि चमकाने के चक्कर में हर साल 2-4 इस तरह के कैम्प लगवाता रहता है और मैट्रो अस्पताल जिसकी अपनी छवि लुटेरे कसाईबाड़े जैसी है, अपने को समाज के प्रति संवेदी दिखाने व अपनी मशहूरी कराने के लिये यहां आकर शिविर की ड्रामेबाज़ी करता है। वैसे भी केवल जांच और वह भी बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों व उपकरणों के कोई मायने नहीं रखती। यदि जांच में बीमारी का थोड़ा बहुत पता चल भी जाय तो उसका लाभ क्या? लाभ तो तब होगा न जब उसका इलाज भी किया जाय। मैट्रो अस्पताल का तो इतना उद्देश्य है कि जेल से छूटने के बाद कैदी उनके यहां कटने के लिये आयें। हां इस ड्रामेबाज़ी का लाभ जेलर को निजी तौर पर जरूर मिलता है। वह जब भी मैट्रो अस्पताल में जाता है तो उसे वीआईपी ट्रीटमेंट और वह भी मुफ़्त मिलता है।

करीब 2500 बंदियों वाली इस जेल में बीमार हो जाने वाले बंदियों की काफ़ी दुर्दशा होती है, कई बार तो मौत भी हो जाती है। इलाज के अभाव में मरे हुये कैदियों को दिखाया जाता है कि अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मरा। कहने को सरकार ने जेल में एक अच्छा-खासा 30 बेड का अस्पताल यानी इमारत बना रखी है। इसमें एक महिला चिकित्सक व एक दंत चिकित्सक सहित 6 डॉक्टरों व अन्य स्टाफ़ रखे जाने का प्रावधान है। इन

जेलर अनिल कुमार : खुद ही बीमार!

डॉक्टरों में से एक एसएमओ (सीनियर मेडिकल अफ़सर) होना चाहिये। परन्तु वास्तव में ले-दे कर एक ही डॉक्टर पक्के तौर पर है जिसका होना न होना बराबर है क्योंकि वह खुद मानसिक रोगी है। दो सेवानिवृत डॉक्टर ठेके पर रखे हुये हैं। इनका भी जब दिल करे आ जायें नहीं तो न आयें। महिला चिकित्सक है नहीं दंत चिकित्सक के नाम पर सीएमओ की ओर से 2-2 दिन के लिये किसी-किसी की तैनाती कर दी जाती है जो अक्सर आते नहीं और कभी आ भी जायें तो कुछ करते नहीं। बहाना यह होता है कि चेयर खराब है, एक्सरे खराब है, फ़लां उपकरण खराब है आदि-आदि।

अन्य स्टाफ़ के नाम पर एक फ़ार्मासिस्ट तो स्थाई तौर पर तैनात है, एक अन्य किसी को खानापूर्ति के लिये 15-15 दिन के लिये तैनात कर दिया जाता है। वह भी कभी कभार ही टाइम पास करने को आ जाता है। शेष अन्य स्टाफ़ के तौर पर कैदियों को ही काम पर लगाया जाता है। रात की ड्यूटी में तो डॉक्टर व फ़ार्मासिस्ट सब कुछ ये कैदी ही होते हैं। बीमारी का पता लगा कर दवा देने से लेकर इन्जेक्शन लगाने तक का काम यही लोग करते हैं। वैसे कानूनन रात की ड्यूटी के लिये डॉक्टर की नियुक्ति का प्रावधान तो है पर रहता कोई नहीं।

डॉक्टर व स्टाफ़ तो जैसा है सो है, दवायें व अन्य साजो-सामान का भी नितांत अभाव रहता है। प्रति दिन 2000 रुपये की दवायें खरीदने का प्रावधान रखा गया है। यह भी स्थानीय परचून विक्रेता से इतनी महंगी खरीदी जाती हैं कि बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती हैं, जबकि इसी रकम से थोक में खरीदारी की जाय तो कहीं अधिक माल उपलब्ध हो सकता है। इस प्रतिदिन वाली खरीद के अलावा जेल विभाग की ओर से क्या सामान आता है कोई नहीं जानता, सब यूं ही दांये-बांये खुर्द-बुर्द हो जाता है। पाठक समझ सकते हैं कि 2500 बंदियों में रोजाना 2000 की दवाइयां कोई मायने नहीं रखती। सक्षम एवं सम्पन्न बंदी तो अपने बल बूते पर बाहर से अपने पैसों से दवा मंगवा लेते हैं परन्तु गरीब भगवान भरोसे ही रहते हैं।

बंदियों को अस्पताल के डॉक्टर द्वारा रैफ़र किये जाने पर जेल से बाहर बीके अस्पताल अथवा अन्यत्र दिखाने का प्रावधान तो है परन्तु इसकी राह में रोड़ा तब अटकता है जब समय पर पुलिस गार्द नहीं मिलती। पलवल ज़िले से सम्बन्धित कैदियों की तो मुसीबत और भी अधिक है। उन्हें बाहरी डॉक्टर के पास ले जाने के लिये पलवल पुलिस गार्द विशेष रूप से आती है जो यदा-कदा ही आती है।

बीके अस्पताल में जैसा इलाज होता है वह तो पाठक जानते ही हैं! इस लिये यहां भी साधारण कैदी धक्के खाकर लौट जाते हैं। हां यदि कैदी एसआरएस ग्रुप जैसे बड़े लुटेरे हों तो उन्हें मैट्रो जैसे पंचतारा अस्पताल में दाखिल कराया जा सकता है।

चिकित्सा के नाम पर जेलर जो कुछ ड्रामेबाज़ी कर रहा है सो कर रहा है परन्तु अपने किये धरे पर वह जो न्यायधीशों की भी मुहर लगवा लेता है, उससे जज साहेबान को बचना चाहिये। इससे उनकी विश्वसनीयता तो कम से कम बची रहेगी। फ़िलहाल जजों की विश्वसनीयता का हाल यह है कि हर ब्लॉक में सैशन जज की ओर से लगी शिकायत पेटिका में भी कोई बंदी अपनी शिकायत नहीं डालता क्योंकि बंदी मानते हैं कि जज भी जेलर से मिले हुये हैं।

दीपक मंगला की दलाली को खट्टर का वरद्हस्त ?

म. मो. (पलवल)- 7 जून को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पलवल में रोड शो के नाम पर तमाशा किया गया जिसमे लगभग पचास से साठ लाख रुपये खर्च होने की बात की जा रही है। इस खर्च में सरकारी महकमो का खर्चा शामिल नहीं है। दो दिन तक मुख्य बाजार में आम लोगों की दैनिक खरीददारी की गतिवधियां लगभग ठप्प कर दी गई थी जिस कारण आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ।

इस तमाशे का उद्देश्य वैसे तो बीजेपी सरकार की चार साल की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार बताया गया था लेकिन वास्तविक उद्देश्य तो आर एस एस के चेहरे, पिछले विधान सभा चुनाव में हारे हुए दीपक मंगला की गिरती हुई साख को बचाने के साथ ही चौटालाओं के दरबार से लेकर बी एस पी तक दर दर भटकने के बाद बी जे पी में शामिल हुए पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल के प्रति अपने पंजाबी भाईचारे को भी दिखाना था। जिस रूट से खट्टर का काफिला गुजरा वहां तो सफाई करवा दी गई लेकिन बाकी शहर आज भी गन्दगी से त्राहि त्राहि कर रहा है।

वैसे इस तमाशे को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने कई दिन से तैयारी की थी लेकिन सरकारी अमले को भी लगाने के बावजूद कोई दो तीन हजार की भीड़ मुश्किल से जुटा पाई। इस तमाशे के लिए पचासों स्कूली बसें गांवों से लोगों को लाने ले जाने के लिए लगाईं गई थीं। जगह जगह शिकंजी ,कोल्ड ड्रिंक्स, हलवा-पूरी, छोले-भटूरे आदि खाने का पूरा प्रबंध किया गया था।

मंगला के गिरते ग्राफ का कारण उनके खासमखास प्रवीण गोयल व मुकेश सिंगला द्वारा सरकारी ठेकों में की जा रही दलाली है। कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में सरकारी ठेके जहाँ करण दलाल उसके परिवार के कृपापात्र ठेकेदारों के पास होते थे वहीं अब ये ठेकेदार मंगला की जाति के हैं जिनसे डील करने का जिम्मा मंगला के खासमखास प्रवीण गोयल व मुकेश सिंगला के पास है। नगर परिषद पलवल व लोक निर्माण विभाग आदि सभी जगह मंगला के लिए ठेकेदारों से तालमेल का कार्य ये दोनों करते हैं।

कहने को तो पलवल में नगर परिषद् है जिसमे चुने हुए पार्षद हैं लेकिन नगर परिषद के ठेकों में कमीशन खोरी के कारण सभी तरह के निर्माण कार्यों में घटिया से घटिया सामग्री लगती हैं जिसकी शिकायत करने पर पहले तो ठेकेदार ही लोगों को धमकाने का कार्य करते हैं और यदि कोई हिम्मत करके शिकायत करे भी तो कहीं कोई सुनवाई नही होती है। पिछले वर्ष जब पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण अपने चरम पर था तो कागजों में पलवल शहर में पच्चीस लाख रुपये का पानी छिड़का दिखा दिया गया जबकि छिड़का दो लाख का भी नहीं। इस बारे में जब कुछ पार्षदों ने आर टी आई के माध्यम से इस घोटाले के बारे में जानकारी ली तो पूरी पोल खुल गई लेकिन पार्षदों को चुपचाप रहने व मुंह न खोलने की धमकी दी गई जिस कारण आवाज उठाने वाले पार्षद भी चुपचाप बैठ गए।

वैसे तो नगर परिषद के अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है और अध्यक्ष भी एक महिला हैं लेकिन वास्तविक कार्य उसका पुत्र करता है जिसके दीपक मंगला के साथ सम्बन्ध जग जाहिर हैं। दीपक मंगला का मुख्य पेशा सूद पर रुपये देने व प्रॉपर्टी डीलिंग का है जो आज भी बदस्तूर जारी है। लोगों का कहना है कि शहर में कई जगह अवैध कालोनी काटी जा रही हैं लेकिन जिनमे मंगला की हिस्सेदारी होती है। वहां पर डी टी पी की झांकने की हिम्मत भी नहीं है।

जब मंगला को आईना दिखाया

हुआ यूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व एक दिन सुबह सुबह दीपक मंगला अपने कुछ खास खास चमचों के साथ जिनमे नगर परिषद की अध्यक्षा के पुत्र व कुछ ठेकेदार थे, को लेकर सिनियर सैकंडरी स्कूल पलवल जहाँ शहर के लोग सुबह शाम सैर करने आते हैं ,आ पधारे। घूमते हुए वे उस जगह पहुंचे जहाँ शहर के कुछ लोग वाक करने के बाद व्यायाम करते हैं और जहाँ पचासों लोग व्यायाम कर रहे थे। वहां पर बात चलते चलते सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होने लगी इसपर वहां उपस्थित एक व्यक्ति से नहीं रहा गया और उसने मंगला को आईना दिखाते हुए कहा कि मंगला जी हरियाणा की जनता ने सन 2014 में बीजेपी को थोक में वोट इसलिए दिए थे कि हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन होगा भ्रष्टाचार भाई भतीजा वाद कमीशन खोरी आदि का खत्म होगा और एक पारदर्शी सरकार आएगी। लेकिन हो क्या रहा है एक भी वादा पूरा नही किया। भ्रष्टाचार कमीशन खोरी, प्रदूषण व गंदगी वैसी ही है जैसी कांग्रेस सरकार में थी गलियों से लेकर सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री लगाईं जा रही है। पच्चीस लाख का पानी कागजों में छिड़का दिखा दिया। इतना सुनते ही मंगला से कोई जबाब तो बना नहीं, बस उन्होंने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप बिना कोई जबाब दिए वहां से चलते बने।

सीवर सिस्टम तो सेक्टर 21 का भी चौपट हुआ पड़ा है, पानी सिस्टम भी!

फ़रीदाबाद (म.मो.) गतांक में नहर पार ग्रेटर फ़रीदाबाद की सोसायटियों के खुले मैदानों में सड़ते सीवेज को लेकर प्रदूषण विभाग के खटराग का कुछ विवरण पेश किया गया था। उसे पढकर सेक्टर 21 के पाठकों ने इस संवाददाता को बुला कर अपने यहां की बेहाल सीवरेज व्यवस्था को मौके पर दिखाया।

विदित है कि सेक्टर 21 ए, बी, सी व डी तमाम 'हूडा' द्वारा विकसित करके बेचे गये हैं। सेक्टर 21 डी को छोड़ कर शेष सारा सेक्टर अति पॉश वीआईपी सेक्टर है। सेक्टर 21 सी के साथ लगते एक भाग में 'हूडा' ने दर्जनों ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को प्लॉट आवंटित किये थे। ये सभी को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटियां हैं। इन सोसायटियों सहित पूरे सेक्टर की सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल चौपट हुई पड़ी है।

सेक्टर 21 सी समतल ज़मीन पर है तथा इसकी पश्चिम दिशा में बनी दर्जनों सोसायटियां अपेक्षाकृत ऊंची पहाड़ियों पर बसी हुई हैं। इनमें से अधिकांश का सीवेज बहा कर 21 सी के एक भूखंड पर छोड़ दिया जाता है। शेष सोसायटियों व पूरे 21 सेक्टर के सीवेज को पाइपों द्वारा 21 बी के पूर्व में रेलवे लाइन के पास लाया जाता है। कहने को तो इस सीवेज को बूस्टर पंपों द्वारा भोपानी क्षेत्र में बने सीवेज ट्रीटमेंट तक पहुंचाया जाता है। परन्तु वास्तव में न तो इस काम के लिये उचित पाइप लाइन है और न ही सही ढंग से काम करने वाले बूस्टर पंप

चार बूंदें क्या बरसीं कि जीवन अस्त-व्यस्त हुआ

फ़रीदाबाद (म.मो.) गये शनिवार शाम को कुछ देर की आंधी के बाद चार बूंद पानी क्या बरसा कि सारा शहर अस्त-व्यस्त हो कर रह गया। सबसे पहले तो बिजली गयी जो फ़िर कई घंटों तक नहीं लौटी। बरसा हुआ पानी सड़कों पर खड़ा हो गया। दरअसल पानी बरसा ही इतना था कि बह कर कहीं जाने लायक नहीं था। यदि ज़्यादा भी बरस जाता तो जो बह कर कहीं जा सकता तो चला जाता परन्तु एक खास मात्रा में तो पानी ने सड़कों पर ही रह कर सूखना होता है क्योंकि सड़कों की बनावट एवं डिजायन ही ऐसा है।

इसके चलते अजरोंदा मोड़ पर अच्छा-खासा जाम लगता है जिसका असर नीलम चौक व अजरोंदा मैट्रो स्टेशन तक पड़ता है। ओल्ड फ़रीदाबाद वाले रेलवे अंडर पास में पानी खड़ा होने से गाड़ियां फ़ंस गयीं और जाम लग गया। यह हाल तो चार बूंद बरसने से है। जब ज़्यादा बरसता है तो पूछो मत। राजमार्ग को ग्रीनफ़ील्ड कॉलोनी से जोड़ने वाले अंडरपास में तो हर साल गाड़ियां डूबती ही हैं।

गत 2 माह से नगर निगम के अधिकारी पूरे ज़ोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं कि करोड़ों रुपये खर्च करके उन्होंने नालों की सफ़ाई करा दी है जिससे इस बार जल भराव की समस्या नहीं होगी। यह कोई नई बात नहीं। हर साल इसी मद में करोड़ों रुपया डकारा जाता है और जल भराव ज्यों का त्यों होता रहता है।

और सबसे बड़ी बात किसी की नीयत ही नहीं कि इस सीवेज का सही ट्रीटमेंट हो। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश सीवेज रेलवे लाइन और इसके ऊपर बने बड़खल वाले फ़्लाइओवर के पास ही सड़ता रहता है।

नहर पार की सोसायटियां एवं फ़्लैट्स क्योंकि प्राइवेट बिल्डरों ने बनाये हैं इसलिये प्रदूषण बोर्ड आये दिन उन पर तो सवार हो जाता है, कभी बिजली-पानी काटने की धमकी देता है तो कभी सीलिंग की। सेक्टर 21 की सड़ता हुआ सीवेज इस प्रदूषण बोर्ड को क्यों दिखाई नहीं देता। वजह बड़ी साफ़ है; प्राइवेट बिल्डर को आंख दिखाने पर कुछ न कुछ सेवा-पानी की संभावना बनती है जबकि सरकार यानी नगर निगम व 'हूडा' वाले तो खुद सेवा-पानी लेने वाले हैं।

इतना ही नहीं गोल्फ़ सोसायटी एवं उसके साथ लगती सोसायटियों के पीछे पेड़ उगाने के लिये जंगलात की संरक्षित जमीन है। इस ज़मीन पर जगह-जगह कूड़े-कचड़े के ढेर सड़ रहे हैं। यह तमाम कूड़ा-कचड़ा आस-पास बने बेंक्वेट हॉल अथवा गार्डनों से आता है। शादी समारोह आदि के दिनों में तो यह गंद और भी बढ जाता है और ज़्यादा सड़ता है। मोदी व खट्टर का स्वच्छता अभियान यहां कोई मायने नहीं रखता।

इन तमाम सोसायटियों की एक बड़ी समस्या पानी की है। सोसायटी में चाहे 50 घर हों या 500 या इससे भी अधिक, पानी का केवल एक ही कनेक्शन दिया जाता है, वह भी पौने इन्च का जबकि सेक्टर या कहीं भी बने एक घर को आधा इन्च का क्नेक्शन दिया जाता है। इसके चलते लगभग सभी सोसायटियों ने अपने यहां गहरे बोर करा कर ट्यूबवैल लगवा लिये। लेकिन अब सरकार इन ट्यूबवैलों को अवैध बता कर बंद करने पर तुली है। यानी न तो सरकार खुद पानी दे रही है और न ही सोसायटी वालों को अपना इंन्तजाम करने दे रही है। कुल मिलाकर सरकार ने तमाम सोसायटियों के लिये यह एक स्थाई समस्या बना रखी है जिसकी कोई सुनवाई नहीं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06